

उत्तर प्रदेश सरकार  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2  
संख्या-1900/43-2-2006-15/2(2)/03 टी.सी.14  
लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2006

### अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या-22, सन्, 2005) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

### **उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) (संशोधन) नियमावली, 2006**

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जाएगी।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम-4, 5 तथा 6 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) नियमावली, 2006 के नियम 4, 5 तथा 6 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4 उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा एस रुपये का आवेदन ज़ुल्क संलग्न किया जाएगा।	4. उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ संबंधित लोक प्राधिकारी को संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा एस रुपये का आवेदन ज़ुल्क संलग्न किया जाएगा।

<p>5. उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, द्वारा निम्नलिखित दरों पर जुल्क प्रभारित किया जाएगा:-</p> <p>(क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागजों में) के लिए दो रुपये,</p> <p>(ख) बृहत्तर आकार के कागजों में किसी प्रतिलिपि का वास्वविक प्रभार या लागत मूल्य,</p> <p>(ग) नमूनों या प्रतिदशों के लिए वास्वविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य,</p> <p>(घ) अभिलखों या प्रतिदशों के लिए प्रथम धण्टे के लिए दस रुपये का जुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रुपये का जुल्क।</p>	<p>5. उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा(1) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, द्वारा निम्नलिखित दरों पर जुल्क प्रभारित किया जाएगा:-</p> <p>(क) सृजित या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागजों में) के लिए दो रुपये,</p> <p>(ख) बृहत्तर आकार के कागजों में किसी प्रतिलिपि का वास्वविक प्रभार या लागत मूल्य,</p> <p>(ग) नमूनों या प्रतिदशों के लिए वास्वविक लागत या मूल्य और जहाँ सूचना निर्धारित मूल्य के प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो वहाँ इस प्रकार नियत किया गया मूल्य,</p> <p>(घ) अभिलखों या प्रतिदशों के लिए प्रथम धण्टे के लिए दस रुपये का जुल्क और तत्पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट के लिए (या उसका आंशिक भाग) पाँच रुपये का जुल्क।</p>
<p>6. धारा-7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा जुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा:-</p> <p>(क) डिस्कट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गई सूचना के लिए प्रति डिस्कट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रुपये, और</p>	<p>6. धारा-7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकारी को सदैव समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा जुल्क निम्नलिखित दरों पर प्रभारित किया जाएगा:-</p> <p>(क) डिस्कट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क में प्रदान की गई सूचना के लिए प्रति डिस्कट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क पचास रुपये, और</p>
<p>(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रुपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।</p>	<p>(ख) मुद्रित रूप में प्रदान की सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन हेतु नियत मूल्य पर या प्रकाशन से उद्धरणों के लिए दो रुपये प्रतिलिपि का प्रति पृष्ठ।</p>

आज्ञा से,

(बी० एम० मीना)  
सचिव



उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली:
- 2- राज्य सूचना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त आयुक्त, उ०प्र० आसन, लखनऊ।
- 5- आधौगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० आसन, लखनऊ।
- 6- समाज कल्याण आयुक्त, उ०प्र० आसन, लखनऊ।
- 7- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमुत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9- समस्त प्रमुख सचिव/सचिवच, उत्तर प्रदेश आसन/प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्यसचिव।
- 10- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त मण्डायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 14- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 15- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को सूचना की अंगेजी रूपान्तरण सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक-27, नवम्बर, 2006 के असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में प्रकाशित करने का कट करे और अधिसूचना की 2000 प्रतियाँ प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय को भीध उपलब्ध कराने का कट करे।
- 16- संसदीय कार्य अनुभाग-1
- 17- उ०प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जगदीश लाल श्रीवास्तव)

संख्या- 993 /43-2-2005

प्रति,

शिरिराम शर्मा,  
प्रमुखा सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सरत प्रमुखा सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

प्रशासनिक सुधार अध्याय-2 संख्या: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2005

विषय: - सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के संबंध में ।

महोदय,

सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12-10-2005 से लागू हो गया है, जिसकी प्रती आधुनिक युग में प्रेषित करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के दृष्टिकोण आधुनिक कार्यवाही हेतु अज्ञात किया जा चुका है ।

2- अधिनियम की धारा 6(1) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो सुचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित अपेक्षा पत्र देगा व ऐसा शुल्क देगा जो निर्धारित किया गया हो ।

3- अधिनियम की धारा 27(2) में सरकार द्वारा तैयार जाने वाले शुल्क के निर्धारण का प्रावधान है जिस हेतु नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है ।

4- उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिकोण से यह कहने का निर्देश हुआ है कि सुचना सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 (1) (बी) (सी) के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से शुल्क निर्धारित करते हुए अज्ञात कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

1. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा-1 के अन्तर्गत सुचना प्राप्त करने हेतु 'गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करनेवाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं' ली जायेगी जिसके लिए उसे प्रमाण पत्र देना होगा।

रु 10-00  
प्रति आवेदन पत्र।

2. लिखित अपेक्षा की प्रतिनिधि हेतु रु-4।  
या रु-3। साइज पेपर पर प्रतिनिधि

रु 2 -00  
प्रतिपृष्ठ।

3. साइज साइज के पेपर पर प्रतिनिधि हेतु

प्रतिपृष्ठ  
व्यय प्रतिपृष्ठ।

4. गैरमाल्य अथवा माउल के लिए उनका वास्तविक मूल्य और 'कम' सुचना छाप मूल्य से संबंधित है यहाँ निर्धारित क्षम मूल्य

---2/

---2---

15. अभिलेखों का निरीक्षण प्रथम घण्टा	₹0 10-00
उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के लिए	₹0 5-00
16. डिस्क्रेट या फ्लायींग या कम्पैक्ट डिस्क द्वारा सूचना प्राप्त करने पर	₹0 50-00
	प्रत्येक।
17. प्रिंटेड सामग्री की सूचना हेतु ऐसे प्रिंटेड सामग्री की प्रकाशक की नियत दर पर	
18. प्रकाशित सामग्री के उद्धरण की प्रतिपृष्ठ फोटोकॉपी के लिए	₹0 2-00
	प्रतिपृष्ठ।

5- उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा संबंधित लोक प्राधिकारी को देकर डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक चेक से लिया जा सकेगा तथा प्रत्यावेदन कर्ता को शुल्क रसीद प्रदान की जायेगी।

6- कृपया अपने अधीन सभी 'विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों' को उक्त से अवगत कराने का कष्ट करें। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने मण्डल एवं जनपद के सभी कार्यालयों को अपने स्तर से भी अवगत करा दें व निर्दिष्ट कर दें कि कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन सभी जन सूचना अधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा दें।

7- यह आदेश पित्त विभाग के अध्यापक सं० ई-9-542/दस-05 दिनांक 17-11-05 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

गिरिराज वर्मा  
प्रमुख सचिव।

संख्या-993/11/43-2-2005 तारीख

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से  
Nandy Swनयोज सिंह  
सचिव।